

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उ०प्र०
(आडिट अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: 22 जुलाई, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय: बन्द फर्मों की जाँच व उनके वादों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

लोक लेखा समिति की विभिन्न बैठकों में महालेखाकार उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया है, कि विभागीय जाँच में फर्म बन्द पाई जाती है अथवा व्यापारी के प्रार्थना पत्र के अनुसार फर्म बन्द हो जाती है, किन्तु उनके कर निर्धारण आदेश अविलम्ब पारित नहीं किए जाते हैं । इस विलम्ब के कारण व्यापारी लापता हो जाते हैं और उनसे वसूली की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाती है । अतः इस संबंध में वैट अधिनियम 2008 के नियम-4 का उपनियम-6 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बन्द फर्मों के मामलों में अविलम्ब कर निर्धारण / वसूली किए जाने के संबंध में निम्न प्रकार से निर्देश जारी किए जाते हैं :-

- 1- जिन मामलों में विभागीय जाँच में फर्म बन्द पायी जाती है अथवा व्यापारी द्वारा फर्म बन्दी की सूचना दी गयी है, ऐसे मामलों में पंजीयन निरस्तीकरण की अविलम्ब कार्यवाही करते हुए व्यापारी के सभी अवशेष वादों का 03 माह के अन्दर निस्तारण कर दिया जाए और मांग सृजित होने की दशा में अविलम्ब वसूली की कार्यवाही की जाए ।
- 2- यदि मासिक रुपपत्र दाखिल करने वाले व्यापारी द्वारा लगातार 03 माहों एवं तिमाही रुपपत्र दाखिल करने वाले व्यापारी द्वारा लगातार 02 त्रैमासों के रुपपत्र व कर जमा नहीं किया गया है, तो उनके व्यापार स्थल की जाँच तुरन्त कर ली जाए और व्यापार बन्द पाए जाने की दशा में पंजीयन की निरस्तीकरण के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही करते हुए सृजित मांग की अविलम्ब वसूली की कार्यवाही करायी जाए तथा व्यापारी के सभी अवशेष वादों का 03 माह के अन्दर निस्तारण कर दिया जाए और सृजित मांग की वसूली के सार्थक प्रयास किए जाए ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और यदि बाद में यह पाया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही न करके विलम्ब से कर निर्धारण किए गए हैं और इस विलम्ब के कारण व्यापारी लापता हो गए हैं व उनसे वसूली की कार्यवाही

सम्भव नहीं हो पा रही है, तो इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इस परिपत्र में दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराना जोनल एडीशनल कमिशनर एवं ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) की जिम्मेदारी होगी।

इस परिपत्र की आवश्यक छायाप्रतियाँ करवाकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को प्राप्त करा दें।

(चन्द्रभानु)

कमिशनर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकर (वाणिज्य एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), उ०प्र० इलाहाबाद / शाखा लखनऊ।
- 3- मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क / कम्प्यूटर / संग्रह / निरीक्षण अनुभागों को 5-5 प्रतियों सहित।
- 4- निदेशक कर एवं प्रशिक्षण संस्थान, विभूति खण्ड, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- आडिट अनुभाग को 25 अतिरिक्त प्रतियाँ।

ज्वाइन्ट कमिशनर (आडिट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।